Regarding privatization of power sector in Rajasthan-Laid

श्री मुरारी लाल मीना (दौसा) : सरकार देश के विद्युत उत्पादन का निजीकरण करने की ओर बढ़ रही है । ऐसा ही एक मामला राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम (RVUNL) और उसकी परिसंपत्तियों के निजीकरण का है । निगम के कर्मचारी कई महीनों से आंदोलनरत हैं और राज्य की जनता को भी इससे गंभीर नुकसान हो सकता है । बिजली क्षेत्र किसी भी राज्य की आधारभूत संरचना का अभिन्न हिस्सा है । RVUNL की कोटा, सूरतगढ़, और छबड़ा जैसी इकाइयों ने सस्ती और सतत बिजली आपूर्ति में अहम योगदान दिया है । केंद्र सरकार की नीतियों और कोयला आपूर्ति में विफलता ने राज्य को महंगा आयातित कोयला खरीदने पर मजबूर किया, जिससे बिजली दरें बढ़ीं । निजीकरण के बाद ये इकाइयाँ केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) के अधीन होंगी, जिससे राज्य का नियंत्रण समाप्त हो जाएगा और जनता महंगी बिजली के लिए मजबूर होगी । निजीकरण से लगभग 4000 कर्मचरियों और 1 लाख से अधिक लोगों की आजीविका पर संकट खड़ा हो जाएगा । इस प्रक्रिया की गोपनीयता ने कर्मचारियों में अविश्वास पैदा किया है । इन निजीकरण प्रयासों को तुरंत रोका जाए और बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए पारदर्शी और जनहितैषी नीतियाँ अपनाई जाएँ । राज्य के नियंत्रण में रहकर बिजली उत्पादन और वितरण का संचालन जनता के हित में होगा ।